मताधिकार फक्त लोकशाहीसाठी | VOTE FOR DEMOCRACY

प्रेस विज्ञप्ति

19 नवंबर, 2024

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 2024 विधानसभा चुनावों में चुनावी हेरफेर और अनियमितताओं के आरोप: वोट फॉर डेमोक्रेसी ड्राफ्ट रिपोर्ट

"भारत में लोकतंत्र दोराहे पर खड़ा है। हम चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी चुनावी प्रणाली की अखंडता खत्म हो रही है। जवाब और सुधार का समय अब आ गया है।"

अपनी सबसे हालिया रिपोर्ट में वोट फॉर डेमोक्रेसी (VFD) ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर 2024 विधानसभा चुनावों की अखंडता पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें चुनावी हेरफेर, वोट प्रतिशत में बेवजह बढ़ोतरी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के परेशान करने वाले आरोपों को उजागर किया गया है। VFD की विस्तृत रिपोर्ट चुनाव डेटा में महत्वपूर्ण विसंगतियों को उजागर करती है, जो सीधे तौर पर भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा चुनावों को कराने में खामियों की ओर इशारा करती है, खासकर मतदान करने वाले व्यक्तियों के वास्तविक आंकड़े जारी करने में इसकी अनिच्छा के संबंध में। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनावों में, निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा के बजाय, ईसीआई द्वारा वोट प्रतिशत के जिलेवार आंकड़े जारी किए गए!

वीएफडी द्वारा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। [1]वीएफडी की रिपोर्ट में मतदान के आंकड़ों में हेरफेर की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का पता चलता है, खासकर हरियाणा में, जहां 5 से 7 अक्टूबर, 2024 के बीच आधिकारिक मतदान में 6.71% की वृद्धि हुई - यह बदलाव अतिरिक्त 1.3 मिलियन वोटों के बराबर है। यह उछाल असामान्य और अस्पष्ट दोनों है, जिससे कुछ राजनीतिक दलों के पक्ष में डेटा में हेरफेर का संदेह पैदा होता है। पंचकूला और चरखी दादरी सहित प्रमुख जिलों में 10% से अधिक की असाधारण मतदान वृद्धि देखी गई, जिससे सभी ने करीबी मुकाबले वाले निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को लाभ पहुंचाया। ये अनियमितताएं आधिकारिक मतदान के आंकड़ों की सत्यता और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में उनकी भूमिका पर सवाल उठाती हैं। **(रिपोर्ट की तालिका 5 देखें; पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है)**

इसके अलावा, ईसीआई ने अपूर्ण वोट गणना जारी करने में विफल रहा है, इसके बजाय जिलेवार मतदान प्रतिशत प्रकाशित करने का विकल्प चुना है। यह जानबूझकर की गई अस्पष्टता चुनावी प्रक्रिया की किसी भी सार्थक जांच को रोकती है। चिंताजनक बात यह है कि 8 अक्टूबर को मतगणना से कुछ घंटे पहले मतदान के आंकड़ों में अंतिम समय में संशोधन विसंगतियों को छिपाने और परिणामों में हेरफेर करने का प्रयास दर्शाता है। इस तरह की हरकतें पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता को कमजोर करती हैं।

इस रिपोर्ट में परेशान करने वाली बातें यह है कि ये विभिन्न बूथों पर ईवीएम वोटों की गिनती में बेमेल होने का संकेत देती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा को मामूली अंतर से जीत मिली। मतदान के बाद पंचकूला (10.52%) और चरखी-दादरी (11.48%) जैसे क्षेत्रों में ईवीएम वोटों में बढ़ोतरी ने खतरे की घंटी बजा दी। इसके अलावा, भाजपा का सिर्फ 10 जिलों में मजबूत प्रदर्शन, जहां उसने 44 में से 37 सीटें जीतीं, बाकी 12 जिलों में उसके खराब प्रदर्शन के बिल्कुल उलट था, जहां उसे 46 में से सिर्फ 11 सीटें मिलीं। इन विसंगतियों को स्थानीय मुद्दों या

[1] चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संकाय के पूर्व डीन डॉ. प्यारा लाल गर्ग, आईआईएम अहमदाबाद के सेवानिवृत्त और भारत के चुनावों की निगरानी के लिए स्वतंत्र पैनल के सदस्य प्रो.सेबेस्टियन मॉरिस और भारत के चुनावों की निगरानी के लिए स्वतंत्र पैनल के सदस्य प्रोफेसर हरीश कार्निक (आईआईटी, कानपुर, (सेवानिवृत्त) वह विशेषज्ञ हैं जिन्होंने गणितीय एक्सट्रापोलेशन के लिए आधार प्रदान किया।

votefordemoc@gmail.com

Dolphy D'souza I +91 98338 84227 | Teesta Setalvad I +91 9967545009

Fr. Frazer Mascarenhas I +91 9324544540 | Khalil Deshmukh I +91 9970265086

मतदाताओं की प्राथमिकताओं से आसानी से नहीं समझा जा सकता है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में मतदान के आंकड़ों में हेरफेर की चिंता बढ़ जाती है। **(रिपोर्ट की तालिका 23 और 24 देखें)**

इस रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनावों में भी अनियमितताओं के पैटर्न का पता लगाया गया है, जहां इसी तरह के अस्पष्ट मतदान में वृद्धि देखी गई थी। लगातार इस तरह के डेटा में हेरफेर चुनाव आयोग की निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की क्षमता पर संदेह पैदा करती है, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है।

हरियाणा में मतदान के आंकड़ों में हेरफेर करने से परिणामों पर सीधा असर पड़ा है, खासकर 17 निर्वाचन क्षेत्रों में जहां जीत का अंतर 5,000 वोटों से कम था। इन कड़े मुकाबलों में बढ़े हुए मतदान के आंकड़ों ने भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में मदद की, जबकि INLD (भारतीय राष्ट्रीय लोक दल) जैसी छोटी पार्टियों को बहुत कम लाभ हुआ। कुल मिलाकर, रिपोर्ट बताती है कि मतदान में हेरफेर ने संभवतः हरियाणा में कम से कम 24 अतिरिक्त सीटों पर भाजपा की जीत में मदद की।

जम्मू-कश्मीर चुनावों में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जहां मतदान प्रतिशत में आखिरी समय में वृद्धि ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इन विसंगतियों की व्यापक प्रकृति दोनों राज्यों में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाती है। **(रिपोर्ट की तालिका 30 देखें)**

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष, चुनावी डेटा में पारदर्शिता और निरंतरता की कमी के साथ, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वीएफडी इन आरोपों की तत्काल और स्वतंत्र जांच की मांग करता है। पारदर्शिता की कमी, डेटा में हेरफेर और रिपोर्ट किए गए मतदान के आंकड़ों में विसंगतियां चुनावी प्रणाली में जनता के विश्वास को बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करती हैं। ईसीआई को सभी अपूर्ण डेटा जारी करने चाहिए, विसंगतियों की व्याख्या करनी चाहिए और इन विसंगतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के चुनावों में इस तरह की हेरफेर न हो।

यह कवायद क्यों महत्वपूर्ण था

यह कवायद विशेष रूप से समय पर किया गया है क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी चुनाव जल्द ही भारत की चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता की पड़ताल करेंगे। जैसे-जैसे नागरिक मतदान करने की तैयारी करते हैं, यह आवश्यक है कि प्रत्येक वोट की सही गणना की जाए और रिपोर्ट की जाए। प्रतिशत के बजाय अपूर्ण मतों की गिनती पर ध्यान केंद्रित करके, पारदर्शिता की मांग यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव का वास्तविक परिणाम स्पष्ट और सत्यापन योग्य हो। वोटों की गिनती, जो सटीक और निश्चित होती है, राउंडिंग त्रुटियों या वोट लीक से जुड़े जोखिमों को समाप्त करती है, जिन्हें प्रतिशत कभी-कभी अस्पष्ट कर सकते हैं। वास्तविक, अपूर्ण मतों की गिनती का प्रकाशन मतदाताओं और चुनाव पर्यवेक्षकों को यह भरोसा करने का अधिकार देता है कि प्रक्रिया लोगों की इच्छा को दर्शाती है, बिना किसी विकृति के।

इसके अलावा, फॉर्म 17-ए और 17-सी का इस्तेमाल, जो वोटों के वास्तविक समय और अंतिम टैली रिकॉर्ड देते हैं, विसंगतियों या हेरफेर के खिलाफ सुरक्षा के रूप में काम करते हैं, उम्मीदवारों और नागरिकों को चुनाव परिणामों की सटीकता को सत्यापित करने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं। यह कार्रवाई की मांग स्थिरता और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी वोट रिकॉर्ड किए जाएं और ईमानदारी से गिने जाएं।

votefordemoc@gmail.com

Dolphy D'souza | +91 98338 84227 | Teesta Setalvad | +91 9967545009
Fr. Frazer Mascarenhas | +91 9324544540 | Khalil Deshmukh | +91 9970265086

झारखंड और महाराष्ट्र में आगामी चुनावों के मद्देनजर यह पहल और भी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को मजबूत करने का मौका देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मतदाताओं की आवाज सुनी जाए और बिना किसी हस्तक्षेप के उनका सम्मान किया जाए। मतदान के सभी चरणों में पारदर्शिता - बूथ-वार लाइन के डेटा से लेकर वीवीपीएटी सत्यापन तक - चुनावी प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो साक्ष्य और मतदान अधिकारी की जवाबदेही की मांग इस पारदर्शिता को और मजबूत करती है, यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया का हर चरण जांच के लिए खुला है।

जैसा कि वीएफडी रिपोर्ट में बताया गया है, चुनावों की ईमानदारी पारदर्शी तरीकों पर निर्भर करती है जो छेड़छाड़, गलत गणना और डेटा हेरफेर को रोकती है। इन राज्य चुनावों में बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए एक स्पष्ट, सटीक और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करना न केवल चुनावों की विश्वसनीयता के लिए बल्कि भारत के लोकतंत्र की सेहत के लिए भी आवश्यक है।

आखिर में, यह स्थापित सिद्धांत है कि मतदाता की सच्ची इच्छा चुनाव के परिणामों में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, हालांकि अनियमित और भ्रष्ट प्रथाओं ने परिणाम को प्रभावित किया है, या मतदाता किसी भी आवश्यक मामले पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी या मजबूरी का शिकार हुआ है, अर्थात, यदि लोगों की इच्छा उनके वोटों में दर्ज की गई 'स्वतंत्र और सच्ची' नहीं है, तो संविधान के अनुच्छेद 324-326 और चुनाव संबंधी कानून और नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, ईसीआई को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन चुनावों का ऐसा अधीक्षण और नियंत्रण केवल चुनावों की घोषणा और संचालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया की 100% शुद्धता की भी आवश्यकता है।

दूसरी वीएफडी ड्राफ्ट रिपोर्ट में हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में जानबूझकर किए गए कदाचार और हेरफेर के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। पूरी रिपोर्ट https://votefordemocracy.org.in/ पर पढ़ी जा सकती है।

डॉल्फी डिसोझा
तीस्ता सेतलवाड़
वोट फॉर डेमोक्रेसी, मुंबई

डॉ.भारत पाटणकर
सतीश लोंढे
लोक मोर्चा, महाराष्ट्र
19 नोव्हेंबर 2024